

न्यायिक नयुक्तियों में देरी चर्चा का वषिय: सर्वोच्च न्यायालय

प्रलिस के लयि:

भरत का सर्वोच्च न्यायालय, कॉलेजयिम प्रणाली, न्यायिक नयुक्तयिँ

मेन्स के लयि:

कॉलेजयिम प्रणाली और इसकी आलोचना

[स्रोत: द हद्वि](#)

चर्चा में क्यँ?

हाल ही में [भरत के सर्वोच्च न्यायालय](#) ने न्यायपालिका में नई प्रतभिओं की नयुक्तयिँ में हो रही देरी को लेकर चर्चा जताई है। इसका प्रमुख कारण उच्च न्यायालयों में न्यायतंत्र का हसिसा बनने के लयि चयनति उम्मीदवारों ने [उच्च न्यायालय कॉलेजयिम](#) की सफारशियों पर कार्रवाई करने में सरकार द्वारा कयि जा रहे वलिंब के परणामस्वरूप अपने आवेदन वापस ले लयि हैं।

- भरत के महान्यायवादी को 9 अक्टूबर, 2023 तक लंबति न्यायिक नयुक्तयिँ और स्थानांतरणों पर अपडेट प्रदान करने का नरिदेश दयि गया था।

न्यायिक नयुक्तयिँ में देरी को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की चर्चाएँ:

- नयुक्तयिँ में वलिंबता तथा प्रतभिओं को अवसर प्रदान करने में चूक:
 - सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के पास 10 महीने से अधिक समय से लंबति 70 उच्च न्यायालय कॉलेजयिम सफारशियों के बैकलॉग को लेकर चर्चा जताई है।
 - सफारशियों को संसाधति करने में इतनी देरी के कारण न्यायपालिका के भीतर प्रतभिओं की कमी हो गई है, क्यँकसिंभावति उम्मीदवार सरकारी नषिक्रयिता के कारण अपनी उम्मीदवारी वापस ले रहे हैं।
 - वधि के कषेत्र में प्रतभिशाली कई लोग इन वलिंबों के कारण उत्पन्न अनश्चितता के कारण भी अपने आवेदन वापस ले रहे हैं।
- नामों का वविदास्पद पृथक्करण:
 - कॉलेजयिम-अनुशंसति सूचयिँ से नामों को अलग करने की सरकार की कार्य-प्रणाली गंभीर चर्चा का वषिय है।
 - कॉलेजयिम द्वारा स्पष्ट मनाही के बावजूद सरकार ने नामों को अलग करना जारी रखा, जसिसे कॉलेजयिम के नरिदेशों का वरिध हुआ।
 - इस वविदास्पद कार्य-प्रणाली के परणामस्वरूप उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी है।
- नयुक्तयिँ और रक्ति पदों का बैकलॉग:
 - उच्च न्यायालय कॉलेजयिम की सफारशियों के व्यापक बैकलॉग ने देश भर में कई न्यायिक पदों को रक्ति छोड़ दयि है।
 - प्रक्रयिा ज्ञापन कॉलेजयिम द्वारा दोहराए गए नामों की शीघ्र नयुक्तिका आदेश देता है, लेकनि इस प्रक्रयिा का पालन नहीं कयि जा रहा है, जसिसे और वलिंब हो रहा है।

Fewer judges, rising cases

Year after year, as vacancies of judges go unfilled, the pendency of cases continues to mount

High Courts (25)

Sanctioned strength of judges
1,114

Working strength of judges:
774

Vacancies:
340

Supreme Court

Sanctioned strength:
34

Working strength:
32

Vacancies:
2



Pendency of cases

In High Courts

60,72,729

Cases pending in High Courts for more than a year

45,22,626 (74.47%)

Cases pending in the Supreme Court

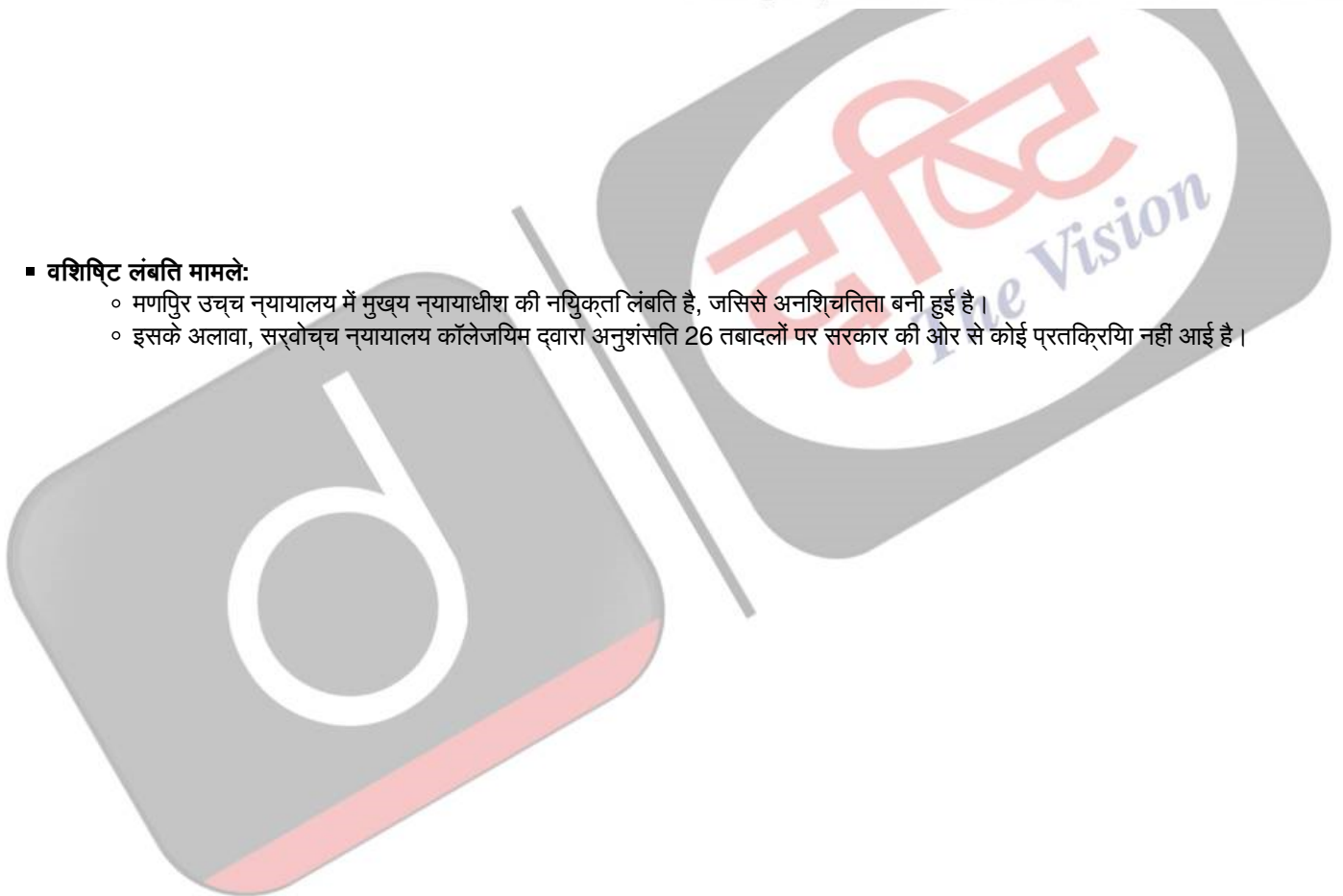
80,591

Courtesy: Department of Justice & National Judicial Data Grid

//

■ वशिष्ठ लंबति मामले:

- मणपुर उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति लंबति है, जिससे अनश्चितता बनी हुई है।
- इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा अनुशंसति 26 तबादलों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।





Collegium System



- System of appointment and transfer of judges
- Evolved through judgments of the Supreme Court, and not by an Act of Parliament

Constitutional Provisions Related to Appointment of Judges

- Articles **124 (2)** and **217**- Appointment of judges to the Supreme Court and High Courts
 - President makes appointments after consulting with "such judges of the Supreme Court and of the High Courts" as s/he may deem necessary.
- But the Constitution does not lay down any process for making these appointments.

Evolution of the System

First Judges Case (1981)

- SC held that in the appointment of a judge of the SC or the HC, the word "consultation" in Article **124 (2)** and in Article **217** of the Constitution does not mean "concurrence"
- Gave the **executive primacy** over the judiciary in judicial appointments

Second Judges Case (1993)

- SC overruled the First Judges Case
- Gave birth to the **Collegium System (Primacy to the Judiciary)**
- Collegium included the Chief Justice of India and the **2** most senior judges of the SC

Third Judges Case (1998)

- SC expanded the Collegium to include the CJI and the **4** most-senior judges of the court after the CJI

Current Structure



Supreme Court Collegium: CJI and the **4** senior-most judges of the SC



High Court Collegium: CJI and **2** senior most judges of the SC

Criticism

- Opaqueness
- Scope for Nepotism
- Exclusion of Executive
- No Predetermined Procedure of Appointment

National Judicial Appointments Commission (NJAC)

- It was an attempt to replace the Collegium System. It prescribed the procedure to be followed by the Commission to appoint judges
- NJAC was established by the **99th** Constitutional Amendment Act, **2014**
- But the NJAC Act was termed unconstitutional and was struck down, citing it as having affected the independence of the judiciary



भारत में न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ:

- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI):
 - भारत के राष्ट्रपति CJI और अन्य SC न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं।
 - जहाँ तक CJI का सवाल है, नवित्तमान CJI अपने उत्तराधिकारी की सफारिश करते हैं।
 - वर्ष 1970 के दशक के अधिक्रमण वविाद के बाद से यह सख्ती से वरषिठता के आधार पर कया गया है।
- सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश:
 - SC के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के ऐसे अन्य न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है, जनिहें वह आवश्यक समझते हैं।
 - CJI और सर्वोच्च न्यायालय के चार वरषिठतम न्यायाधीशों का एक पैनल, जसिे कॉलेजियम के नाम से जाना जाता है, राष्ट्रपति को SC जज के रूप में नियुक्त होने वाले उम्मीदवारों के नामों की सफारिश करते हैं।
- उच्च न्यायालयों (HC) के मुख्य न्यायाधीश और HC के न्यायाधीश:
 - HC के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा CJI और संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद की जाती है।
 - उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सफारिश CJI और दो वरषिठतम न्यायाधीशों वाले कॉलेजियम द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लयि संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श कया जाता है।
 - उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लयि कसिी नाम की सफारिश करने से पहले अपने दो वरषिठतम न्यायाधीशों से परामर्श करना भी आवश्यक है।

आगे की राह

- सरकार को नियुक्तियों के बैकलॉग को खत्तम करने और रक्ति न्यायिक पदों को तुरंत भरने के लयि लंबित उच्च न्यायालय कॉलेजियम सफारिशों के प्रसंस्करण में तेज़ी लानी चाहयि।
- सरकार को कॉलेजियम की सफारिशों से नामों को अलग करने की प्रथा बंद करनी चाहयि और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कॉलेजियम के नरिदेशों का पालन करना चाहयि।
- न्यायिक नियुक्तियों और तबादलों की प्रगत पर नज़र रखने एवं रपिाट करने हेतु एक पारदर्शी प्रणाली स्थापति करना। अनुचति वलिंब या गैर-अनुपालन के लयि ज़मिेदार व्यक्तियों को दोषी ठहराना।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वतित्त वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजयि। (2017)